



भारत का राजपत्र The Gazette of India

असाधारण

EXTRAORDINARY

भाग I—खण्ड 1

PART I—Section 1

प्राधिकार से प्रकाशित

PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 330]

नई दिल्ली, बुधवार, दिसम्बर 12, 2001/अग्रहायण 21, 1923

No. 330]

NEW DELHI, WEDNESDAY, DECEMBER 12, 2001/AGRAHAYANA 21, 1923

वाणिज्य एवं उद्योग मंत्रालय

(वाणिज्य विभाग)

अधिसूचना

नई दिल्ली, 12 दिसम्बर, 2001

विषय : यूरोपीय संघ क्षेत्र, ब्राजील, जापान, कोरिया गणराज्य, सिंगापुर तथा थाइलैंड से पोली-आइसो-बुटिलीन के आयातों से संबंधित पाटनरोधी जांच—प्रारंभिक निष्कर्ष

सं. 47/1/2001-डीजीएडी.— वर्ष 1995 में यथा संशोधित सीमाशुल्क टैरिफ अधिनियम,

1975 और सीमाशुल्क टैरिफ (पाटित वस्तुओं की पहचान, उन पर पाटनरोधी शुल्क का आकलन

एवं संग्रहण और क्षति निर्धारण) नियम, 1995 को ध्यान में रखते हुए:

क. क्रियाविधि

जांच के संबंध में निम्नलिखित क्रियाविधि का पालन किया गया है:-

- निर्दिष्ट प्राधिकारी को उपरोक्त नियमों के तहत मै0 कोठारी शुगर्स एंड कैमिकल्स लि0, मनाली, चेन्नई से लिखित में आवेदन प्राप्त हुआ है जिसमें यूरोपीय संघ क्षेत्र, ब्राजील, जापान, कोरिया गणराज्य, सिंगापुर तथा थाइलैंड (जिन्हें इसके बाद सम्बद्ध देश कहा गया है), के मूल के अथवा वहां से निर्यातित पोली-आइसो-बुटिलीन (जिसे इसके बाद सम्बद्ध वस्तु कहा गया है) के पाटन का आरोप लगाया गया था ।

- ii. प्राधिकारी ने याचिकाकर्ता द्वारा प्रस्तुत किए गए पर्याप्त साक्ष्य के आधार पर यह निर्णय लिया कि सम्बद्ध देशों से पोली-आइसो-बुटिलीन के आयातों के विरुद्ध जांच शुरू की जाए। प्राधिकारी ने नियमों के उप-नियम 5(5) के अनुसार जांच की कार्यवाही करने से पहले पाटन के आरोप प्राप्त होने के बारे में सम्बद्ध देशों के दूतावासों को सूचित किया।
- iii. प्राधिकारी ने दिनांक 12 सितम्बर, 2001 को एक सार्वजनिक सूचना जारी की जिसे भारत के राजपत्र, असाधारण, में प्रकाशित किया। जिसके द्वारा सम्बद्ध देशों के मूल के अथवा वहां से निर्यातित पोली-आइसो-बुटिलीन, जिसे सीमाशुल्क टैरिफ अधिनियम, 1975 के अध्याय 39 के तहत सीमाशुल्क उप-शीर्ष 3902.20 के अंतर्गत वर्गीकृत किया गया है, के आयातों से संबंधित पाटनरोधी जांच शुरू की गई।
- iv. प्राधिकारी ने सार्वजनिक सूचना की एक प्रति सभी ज्ञात निर्यातकों (जिनके ब्यौरे याचिकाकर्ताओं ने उपलब्ध करवाए थे) तथा उद्योग संघों को भेजी और उन्हें नियम 6(2) के अनुसार अपने विचार लिखित में अवगत कराने का अवसर प्रदान किया।
- v. प्राधिकारी ने सार्वजनिक सूचना की एक प्रति सम्बद्ध देशों के ज्ञात आयातकों (जिनके ब्यौरे याचिकाकर्ताओं द्वारा उपलब्ध कराए गए थे) को भेजी और उन्हें पत्र की तारीख से चालीस दिनों के भीतर अपने विचारों से लिखित रूप में अवगत कराने का सुझाव दिया।
- vi. केन्द्रीय उत्पाद शुल्क तथा सीमाशुल्क बोर्ड (सीबीईसी) से सम्बद्ध वस्तुओं के पिछले तीन वर्षों के आयातों के ब्यौरे उपलब्ध कराने का अनुरोध किया गया था।
- vii. प्राधिकारी ने नियम 6(4) के अनुसार याचिका की एक प्रति ज्ञात निर्यातकों तथा सम्बद्ध देशों के दूतावासों का उपलब्ध करवाई।
- viii. प्राधिकारी ने नियम 6(4) के अनुसार संबंधित सूचना प्राप्त करने के लिए सम्बद्ध देशों के निम्नलिखित ज्ञात निर्यातकों को प्रश्नावली भेजी:-
 - मै0 बी0पी0 कैमिकल्स लि0, स्कॉटलैंड
 - मै0 डायालिम कारपोरेशन, सियोल, कोरिया
 - मै0 एक्सोन कैमिकल कंपनीज, न्यू जर्सी, यूएसए
 - मै0 आइडैमिट्सू पैट्रो-कैमिकल्स कारपोरेशन लि0, जापान
 - मै0 बी0पी0 कैमिकल्स एसएनसी, पैरिसलाडीफैंस
 - मै0 एक्सोन कैमिकल, सिंगापुर

- मै0 बीएएसएफ, जर्मनी
 - मै0 एक्सोन मोविल सिंगापुर प्रा0 लि0, सिंगापुर
- सम्बद्ध वस्तु के निम्नलिखित निर्यातकों ने उत्तर दिया:

- मै0 बीएएसएफ, जर्मनी
- मै0 डायलिन्स कारपोरेशन, सियोल, कोरिया

ix. सम्बद्ध देशों के नई दिल्ली स्थित दूतावासों को नियम 6(2) के अनुसार जांच की शुरुआत करने के बारे में इस अनुरोध के साथ सूचना भेजी गई कि वे अपने-अपने देशों के निर्यातकों/उत्पादकों के निर्धारित समय के अंदर प्रश्नावली का उत्तर देने की सलाह दें। निर्यातक को भेजे गए पत्र, याचिका तथा प्रश्नावली की एक प्रति ज्ञात निर्यातकों/उत्पादकों की एक सूची के साथ सम्बद्ध देशों के दूतावासों को भी भेजी गई।

x. भारत में सम्बद्ध वस्तुओं के निम्नलिखित ज्ञात आयातकों तथा उपभोक्ताओं को नियम 6(4) के अनुसार आवश्यक जानकारी मंगाने के लिए एक प्रश्नावली भेजी गई:-

- मै0 भारत शीट लि0, महाराष्ट्र
- मै0 गल्फ इंडिया लि0 दादरा नागर हवेली
- मै0 भारत पेट्रोलियम कारपोरेशन लि0, मुंबई
- मै0 आईबीपीकं0 लि0, कलकत्ता
- मै0 इंडियन एडीटिव्स लि0, मनाली, चेन्नई
- मै0 लुब्रीजोल इंडिया लि0, थाणे
- मै0 हिन्दुस्तान पेट्रोलियम कारपोरेशन लि0, पश्चिम बंगाल
- मै0 केस्ट्रोल इंडिया लि0, मुंबई
- मै0 पेन्नजोइल क्वेकर स्टेट इंडिया लि0, नवी मुंबई
- मै0 महाराष्ट्र पोलीबुटेन्स लि0, नवी मुंबई
- मै0 गुजरात पोलीसिंथीज लि0, बड़ोदरा
- मै0 कोचीन रिफाइनरी बालमेर लारी लि0, केरल
- मै0 इंडियन ऑयल कारपोरेशन लि0, मुंबई तथापि, सम्बद्ध वस्तुओं के निम्नलिखित आयातकों/उपभोक्ताओं ने उत्तर दिया:

- मै0 लुब्रीजोल इंडिया लि0, थाणे
मै0 इंडियन एडीटिव्स लि0, मनाली, चेन्नई
- xi. याचिकाकर्ता से उत्पादन लागत सहित क्षति के मानदण्डों से संबंधित अतिरिक्त सूचना मांगी गई थी, जो प्राप्त हो गई थी ;
- xii. प्राधिकारी ने विभिन्न हितबद्ध पार्टियों द्वारा प्रस्तुत किए गए साक्ष्यों के अगोपनीय अंश प्राधिकारी द्वारा रखी गयी सार्वजनिक फाइल के रूप में उपलब्ध रखे और उसे हितबद्ध पार्टियों द्वारा निरीक्षण के लिए खुला रखा ।
- xiii. सामान्यतः स्वीकृत लेखा सिद्धांतों (जीएएपी) और याचिकाकर्ता द्वारा दी गयी सूचना के आधार पर भारत से संबद्ध वस्तु के उत्पादन की ईष्टतम लागत और माल को बनाने तथा बेचने की लागत का हिसाब लगाने के लिए घरेलू उद्योग की मौके पर जांच सहित लागत जांच भी की गयी ताकि यह पता लगाया जा सके कि क्या डम्पिंग मार्जिन से कम पाटनरोधी शुल्क लगाने से घरेलू उद्योग की क्षति दूर हो सकेगी ।
- xiv. *** यह चिह्न इस अधिसूचना में किसी हितबद्ध पार्टी द्वारा गोपनीय आधार पर दी गयी सूचना तथा नियमों के अंतर्गत प्राधिकारी द्वारा उसे ऐसा माने जाने का द्योतक है ।
- xv. यह जांच 1 अप्रैल, 2000 से 31 अगस्त, 2000 तक की अवधि के लिए की गयी थी ।

याचिकाकर्ता के विचार

2. याचिकाकर्ताओं ने निम्नलिखित मुद्दे उठाए हैं-

- क) सम्बद्ध देशों से पोली-आइसो-बुटिलीन के आयातों में सम्पूर्ण अर्थों में पर्याप्त वृद्धि हुई है। अकेले इंडियन ऑयल कारपोरेशन लि0 द्वारा ही चालू वर्ष में किए गए आयातों की मात्रा निर्यातकों द्वारा उद्धृत कीमतों को देखते हुए 2700 मी0 टन होगी ।
- ख) सम्बद्ध देशों से निर्यात कीमत में काफी गिरावट आई है । इसके अतिरिक्त अमरीकी डालर में निर्यात में कमी (जो निर्यातकों के लिए बहुत महत्वपूर्ण है) भारतीय रुपए की अपेक्षा बहुत अधिक है । मै0 इंडियन ऑयल कारपोरेशन लि0 ने हाल ही में भारत में तीन स्थानों में अर्थात् ट्राम्बे, चेन्नई और कलकत्ता में इस उत्पाद की खरीद करने के लिए अंतर्राष्ट्रीय टैंडर भरे हैं । इन टैंडरों में इन निर्यातकों द्वारा उद्धृत की गई कीमतों का स्तर बहुत कम है जिससे इन देशों में इस उत्पाद के किसी भी उत्पादक को अपनी उत्पादन लागत की वसूली नहीं हो सकती है ।

ग) घरेलू उद्योग की बिक्री कीमत जो 2000-01 तक बढ़ती रही, वह 2001-02 में काफी कम हो गई। इसके अतिरिक्त 1999-2000 की तुलना में 2000-01 में बिक्री कीमत में वृद्धि उत्पादन लागत में हुई वृद्धि से काफी कम थी जिसके परिणामस्वरूप घरेलू उद्योग को काफी वित्तीय हानि हुई।

घ) पाटित आयातों के कारण बाजार में घरेलू उद्योग को कीमत में भारी कटौती करनी पड़ रही है। जो कीमत हाल ही में निर्यातकों ने टैंडर में उद्धृत की थी, उससे लाभ तो क्या, उत्पादन की लागत भी वसूल नहीं होती है। निर्यातकों द्वारा उद्धृत की गई कीमतों से भारतीय बाजार में कीमत में भारी कमी/गिरावट आई है। हाल ही में निर्यातकों द्वारा भरे गए टैंडरों में उद्धृत कीमत से घरेलू उद्योग की बिक्री में काफी कमी आएगी।

ड.) देश में पाटन के फलस्वरूप घरेलू उद्योग को अपनी कीमतें उत्पादन लागत से भी कम करने के लिए बाध्य होना पड़ा। घरेलू उद्योग की वित्तीय स्थिति काफी बिगड़ गई है। घरेलू उद्योग को लाभ की स्थिति से हट कर वित्तीय हानियों की स्थिति का सामना करने के लिए बाध्य होना पड़ा है।

(ग) निर्यातकों, आयातकों और अन्य हितबद्ध पक्षों के विचार

3. निर्यातकों के विचार

- i) मैसर्स बीएसएफ अक्टिंग्सैल्स चाफ्ट, जर्मनी ने अनुरोध किया है कि शिकायतकर्ता द्वारा उत्पादित उत्पाद गैट पाटनरोधी कोडैक्स क अर्थ में एक समान उत्पाद नहीं है। बीएसएफ उत्पाद की गुणवत्ता भिन्न है और आयातित उत्पाद को स्थानीय रूप से उत्पादित उत्पाद द्वारा प्रतिस्थापित नहीं किया जा सकता है। इस तथ्य का उनके ग्राहक मैसर्स इंडियन एडीटिक्स लि० (आईएलए) द्वारा उजागर किया जाएगा जो भारत में बीएसएफ उत्पाद का अनन्य रूप से आयात करता है। चेवरोन ओटोनाइट और बीएसएफ के बीच एक संविदा है जो अंतिम गतव्य के संबंध में कीमत भिन्नता नहीं करता है। इस प्रकार की संविदा से पाटन संभव नहीं है क्योंकि चेवरोन ओटोनाइट ईयू बाजार के लिए भी खरीद करता है।

ii) मैसर्स डायलिम इंडस्ट्रीज कं० लि०, कोरिया

मैसर्स डायलिम ने निम्नलिखित अनुरोध किया है :

(क) याचिकाकर्ता की स्थिति के संबंध में

भारत में पॉलि-आइसो-बुटाइलीन के चार संयंत्र हैं और अकेले याचिकाकर्ता मैसर्स कोठारी कैमिकल्स लि० सबद्ध वस्तु के उत्पादन का 25 % से अधिक उत्पादन का प्रतिनिधित्व करता है और उसके पास याचिका दायर करने का आधार नहीं है।

(ख) क्षति के बारे में

- i) 2000 के आरंभ से आयातों में बेतहाशा वृद्धि हुई है यद्यपि आयात कर की दर काफी अधिक अर्थात् 35 % है। उन्हें भारतीय उत्पादकों की तुलना में आर्थिक माप तथा उत्पाद की गुणवत्ता का प्रतिस्पर्धी लाभ प्राप्त है, और अपनी पॉली-आइसो-बुटाइल प्रौद्योगिकी है। उनकी पॉली-आइसो-बुटाइलीन की उत्पादन लागत भारतीय उत्पादकों की उत्पादन लागत से कम है। इसलिए वे निविदा व्यापार का लाभ प्राप्त कर सकते थे।
- ii) यद्यपि याचिकाकर्ता का यह दावा है कि आयातित वस्तु से घरेलू उद्योग का क्षति हुई है, लेकिन डेलिम पॉजी-आइसो-बुटाइलीन का भारतीय वायु प्रदूषण के संरक्षण में और मुख्य आयातकों समेत भारतीय लुब्रीकेंट्स ऑयल विनिर्माताओं को संरक्षण देने में योगदान है।
- iii) यद्यपि 1999 और 2000 वित्तीय वर्ष के बीच नेफ्था की कीमतों में नाटकीय ढंग से वृद्धि हुई है तथापि विश्वभर में वेशी आपूर्ति की वजह से पॉली आइसो बुटाइलीन की भारतीय घरेलू और अंतर्राष्ट्रीय कीमतों में वृद्धि नहीं हुई है। याचिकाकर्ता को आयातित सामान से नुकसान नहीं हुआ क्योंकि उन्हें भी बाजार में मौजूद इसी तरह की स्थिति से नुकसान हुआ।

(ग) टैरिफ वर्गीकरण

पॉलि-आइसो-बुटाइलीन सीमाशुल्क टैरिफ अधिनियम के अंतर्गत 3902.20 और 3902.90 के रूप में वर्गीकृत है जो कोरियाई एचएस कोड के समान है। हम हमेशा 3902.90 का प्रयोग करके विदेशों का पॉलि-आइसो-बुटाइलीन का निर्यात करते हैं। आमतौर पर पॉलि-आइसो-बुटाइलीन की कीमत 3902.20 के सभी उत्पादों की औसत कीमत से कम है क्योंकि एचआरपीआईबी और अर्ध ठोस पीआईबी अधिक कीमती हैं। 3902.20 के अंतर्गत पॉलि-आइसो-बुटाइलीन का विभाजन पीआईबी के निम्नलिखित तीन किस्मों में किया जा सकता है।

उत्पाद	गुण-तत्त्व
पीआईबी	द्रव, निम्न एम०डब्ल्यू०
एचआरपीआईबी	उच्च रिफ़िनेटिव पीआईबी
अर्ध-ठोस पीआईबी	रबड़ वाला फेज, उच्च एम०डब्ल्यू०

याचिका में यूरोपीय यूनियन में हुए आयातों के आधार पर मात्रा, कीमत और सामान्य मूल्य समेत याचिकाकर्ता के दावे की पुष्टि करने की जरूरत है। हमारे आंकड़े यह दर्शाते हैं कि भारत को किए गए निर्यात की मात्रा 2,267 मि०टन है जबकि याचिकाकर्ता ने जाँच अवधि में मात्र 1,377 मी.टन का ही दावा किया है।

4. अन्य हितबद्ध पक्षों के विचार

i) मैसर्स पेट्रोकेमिकल्स कारपोरेशन लि० (आईपीसीएल), गुजरात

मैसर्स आईपीसीएल जो संबद्ध वस्तु का एक विनिर्माता है, ने याचिका का समर्थन करते हुए कहा है कि विगत कुछ वर्षों में पीआईबी का काफी आयात हुआ है। आयातों की कीमत इतनी कम है कि फीड स्टॉक की घरलू कीमत और कन्वर्सन लागत पर उनका मार्जिन बहुत कम है। भारतीय तेल निगम द्वारा प्रदत्त हाल ही की निविदाओं में निर्यातकों ने काफी कम कीमत उद्धृत की है जिनकी बराबरी करने के लिए यदि उन पर दबाव डाला जाय तो उनका मार्जिन उस स्तर तक कम हो जाएगा जिस स्तर पर व्यापार की व्यवहार्यता पर प्रश्न चिह्न लग सकता है। पाटन के कारण भारतीय उद्योग को काफी क्षति हो रही है। हालात यह हैं कि संबद्ध देशों से हुए पारित आयातों पर तत्काल पाटनरोधी शुल्क लगाने की जरूरत है।

ii) मैसर्स कोची रिफायनरीज लि०

संबद्ध देश में संबद्ध वस्तु के एक विनिर्माता मैसर्स कोची रिफायनरीज लि० ने मैसर्स कोठारी सुगर एण्ड कैमिकल्स लि० द्वारा पाटनरोधी याचिका का समर्थन किया है। प्रश्नावली के उत्तर में उन्होंने लागत संबंधी ब्यौरे प्रस्तुत किए हैं और निम्नलिखित अनुरोध किए हैं :-

(क) भारतीय बाजार में विदेशी एजेंसियों द्वारा इस उत्पाद का पाटन करने के कारण उन्हें अपनी कीमती उत्पादन लागत से काफी कम करनी पड़ी ताकि संयंत्र को चालू रखने के लिए आयातित उत्पाद

की पहुँच के बराबर कीमत रखी जा सके। उन्हें भारत में प्रमुख विपणन कम्पनियों द्वारा प्रदत्त निविदाओं में विदेशी कम्पनियों द्वारा की गई कीमतों की पेशकश के बराबर करने हेतु कीमतों में नाटकीय ढंग से कटौती करनी पड़ी।

(ख) वित्तीय वर्ष 2000-2001 के दौरान उन्हें लगभग 100 करोड़ रुपये के कुल कारोबार की तुलना में लगभग 10 करोड़ रुपये का निवल घाटा हुआ। वे बाजार के कड़े दबाव के कारण संबद्ध वस्तु की बिक्री कुल उत्पादन लागत से कम कीमत पर ^{की} रह है।

5. आयातकों के विचार

i) मैसर्स इंडियन एडीटिब्ज लि०, चेन्नई

मैसर्स इंडियन एडीटिब्ज लि० ने अनुरोध किया है कि उन्होंने परम्परागत पीआईबी का इस्तमाल वर्ष 1999 के अंत तक किया है। इस उत्पाद के विनिर्माण से बेहतर मितव्ययिता और गुणवत्ता की वजह से अब वे इसके स्थान पर दूसरे उत्पाद एचआरपीआईबी उच्च रिएक्टिव पीआईबी का प्रयोग कर रहे हैं। यद्यपि एचआरपीआईबी प्रौद्योगिकी, भौतिक रसायनिक गुण, एवं अनुप्रयोगों के अनुसार एकदम भिन्न उत्पाद है तथापि इसका सीमाशुल्क टैरिफ वर्गीकरण याचिकाकर्ता कम्पनी द्वारा विनिर्मित परम्परागत पीआईबी के वर्गीकरण के समान है। एचआरपीआईबी का भारत में न तो विनिर्माण किया जाता है और न ही इसकी प्रौद्योगिक उपलब्ध है। अतः उन्होंने एचआरपीआईबी को मौजूदा पाटनरोधी जांच के दायरे से बाहर रखने का अनुरोध किया है क्योंकि यह एक भिन्न उत्पाद है और यह किसी भी तरह याचिकाकर्ता कम्पनी समेत घरेलू विनिर्माताओं का प्रभावित नहीं करता है। तथापि आयातक ने निर्धारित प्रश्नावली के अनुसार पूर्ण और ब्यौरा प्रस्तुत नहीं किया है।

ii) मैसर्स लुब्रिजोल इंडिया प्रा. लि.

मैसर्स लुब्रिजोल ने सूचित किया है कि उन्होंने जांच अवधि के दौरान संबद्ध वस्तु का आयात नहीं किया है। तथापि उन्होंने कहा है कि निम्न कारणों की वजह से वे पीआईबी पर पाटनरोधी शुल्क लगाए जाने के मामले का समर्थन नहीं करते हैं :-

(क) अंतर्राष्ट्रीय बाजार में बेशी क्षमता उपलब्ध है और कीमते अंतर्राष्ट्रीय रूप से काफी प्रतिस्पर्धी हैं। स्थानीय ग्राहकों के लिए पॉलिबुटेन्स की वर्तमान आयात कीमत सही प्रतिस्पर्धी कीमत हैं। अन्तर्राष्ट्रीय

रूप से इस उत्पाद की किस्म बाजार में परिवर्तन हानि के कारण अधिकांश पेट्रोलियम फीड स्टॉक में वृद्धि होने के कारण पोलिबुटेन्स का फीड स्टॉक के आयात आगे और सस्ते होंगे जिससे एक निश्चित अवधि में कीमते कम हो जाएंगी।

(ख) पॉलिबुटेन्स के बड़े आपूर्तिकर्ता अर्थात् मैक्स इंडियन पेट्रोकेमिकल्स कारपोरेशन लि० (भारत सरकार का उपक्रम) ने ऐसा कोई पाटनरोधी मामला नहीं उठाया है। जब कभी सरकार द्वारा किसी पाटनरोधी शुल्क पर विचार किया जाता है तो उद्योग द्वारा किए गए दावों की जांच भी की जाती है और यह तथ्य ध्यान में रखा जाता है कि ऐसी कार्रवाई से ग्राहक/जनता को नुकसान न हो।

(घ) उठाए गए मुद्दों की जांच

6 निर्यातकों, आयातकों, याचिकाकर्ता और अन्य हितबद्ध पक्षों द्वारा किए गए अनुरोधों की जांच की गई, उन पर विचार करके इसके बाद नीचे जहाँ आवश्यक हुआ वहाँ उन पर उचित कार्रवाई की गई है।

(ङ.) विचाराधीन उत्पाद

7. (क) वर्तमान याचिका में शामिल उत्पाद यूरोपीय यूनियन के क्षेत्र, ब्राजील, जापान, कोरिया, गणराज्य, सिंगापुर और थाइलैण्ड मूल की अथवा वहाँ से निर्यातित पोलि-आइसो-बुटाइलीन हैं जिस पीआईबी अथवा पोलि-आइसो-बुटाइन (जिस इसके बाद संबद्ध वस्तु कहा जाएगा) भी कहा जाता है। पीआईबीसी-4 ओलिफिन्स स्ट्रीम जो मुख्यतः आइसोबुटीन का बना होता है, के पालिमराइजेशन विनिर्मित सिंथेटिक हाइड्रोकार्बन है। पीआईबी का अनुप्रयोग विभिन्न क्षेत्रों जैसे ल्यूब्रिकैंट्स, एडीटिव्स, केवल फिलिंग कम्पाउण्ड्स, रबड़, मोडिफायर्स, लेडर कैमिकल्स, 2टी ऑयल फार्मूलेशन्स, ऑयलइन्सुलेटर्स एडहेसिव इत्यादि में किया जाता है। वर्तमान जांच में पीआईबी की सभी किस्में शामिल हैं।

(ख) पीआईबी का वर्गीकरण सीमाशुल्क टैरिफ अधिनियम, 1975 के अध्याय 39 के तहत सीमाशुल्क उप-शीर्ष सं० 3902.20 के तहत किया गया है।

(ग) तथापि, यह वर्गीकरण केवल संकेतात्मक है और यह मौजूदा जांच के दायरे पर किसी भी तरह से बाध्यकारी नहीं है ।

घ. समान वस्तु

8. पाटनरोधी नियमों के नियम 2(घ) में यह उल्लेख है कि "समान वस्तु" का तात्पर्य किसी ऐसी वस्तु से है जो जांच के अधीन उत्पाद से हर प्रकार से समरूप या समान है अथवा ऐसी वस्तु के अभाव में ऐसी किसी अन्य वस्तु से है जिसकी विशेषताएं जांच के अधीन वस्तुओं से काफी मिलती-जुलती हैं ।

मै0 बी ए 'एस एफ, जर्मनी के इस दाव के उत्तर में कि उनके द्वारा निर्यातित उत्पाद याचिकाकर्ता द्वारा उत्पादित उत्पाद से भिन्न हैं, प्राधिकारी का मानना है कि एच आर पी आई बी कोई और उत्पाद नहीं है बल्कि पोलि आइसो बुटालिन ही है क्योंकि उत्पाद की भौतिक और रासायनिक विशेषताएं, उत्पाद विनिर्देशन, कार्य और उपयोग एक जैसे हैं । एच आर पोलि-आइसो-बुटालिन और पोलि-आइसो-बुटालिन का एक-दूसरे के स्थान पर उपयोग किया जा रहा है । एच आर पोलि-आइसो-बुटालिन पोलि-आइसो-बुटालिन की ही एक किस्म है और इस प्रकार यह जांच के अधीन उत्पाद और घरेलू उद्योग द्वारा विनिर्मित उत्पाद के समान वस्तु है ।

उपरोक्त को देखते हुए प्राधिकारी का मानना है कि घरेलू उद्योग द्वारा उत्पादित पोली-आइसो-बुटालिन और संबद्ध देशों से आयातित की जा रही पोली-आइसो-बुटालिन का एक दूसरे के स्थान पर उपयोग किया जा सकता है और इस प्रकार ये वाणिज्यिक और तकनीकी रूप से प्रतिस्थापनीय हैं और इस प्रकार नियमों के अर्थों के भीतर ये समान वस्तु हैं।

घ. घरेलू उद्योग

9 उक्त याचिका मै0 कोठारी शुगर्स एंड कैमिकल्स लि0, मनाली, चन्नई द्वारा दायर की गयी है। जांच अवधि के दौरान याचिकाकर्ता का भारत में संबद्ध वस्तु के घरेलू उत्पादन का 25 प्रतिशत से अधिक का हिस्सा बनता है। इसके अलावा, जांच शुरूआत के बाद संबद्ध वस्तु के दो भारतीय विनिर्माताओं नामतः मैसर्स कोची रिफाइनरिज लि0 और मै0 इंडियन पेट्रो कैमिकल्स कारपोरेशन लि0 (आई पी सी एल) ने संबद्ध ^{देशों से संबद्ध} वस्तु के आयात पर पाटनरोधी शुल्क लगाने हेतु उक्त याचिका का अपना समर्थन प्रदान किया है। तदनुसार, प्राधिकारी का मानना है कि याचिकाकर्ता नियम 5(क) और (ख) और नियम 2(ख) के तहत यथा अपेक्षित घरेलू उद्योग की आर स याचिका दायर करने के अपेक्षित मानदण्ड को पूरा करता है।

ज. सामान्य मूल्य, निर्यात कीमत और पाटन मार्जिन

10 धारा 9(क) (1) (ग) के अधीन किसी वस्तु के संबंध में सामान्य मूल्य का अर्थ है:-

- (i) सामान्य व्यापार के दौरान समान वस्तु के लिए उपधारा (6) के अंतर्गत बने नियम के अनुसार यथा निर्धारित तुलनात्मक मूल्य जबकि ऐसी वस्तु निर्यातक देश या क्षेत्र में उपभोग के लिए आशयित हो, या
- (ii) जहाँ निर्यातक देश या क्षेत्र के घरेलू बाजार में सामान्य व्यापार के दौरान समान वस्तु की कोई बिक्री नहीं हो या विशेष बाजार दशा के कारण अथवा निर्यातक देश या क्षेत्र के घरेलू बाजार में बिक्रियों की कम मात्रा के कारण ऐसी बिक्रियों की वजह से समुचित तुलना नहीं हो सकती हो तो सामान्य मूल्य निम्नलिखित में से कोई एक होगा,
- (iii) निर्यातक देश या क्षेत्र से या किसी उचित तीसरे देश से आयात किए जाने पर समान वस्तु का उप-धारा (6) के अंतर्गत बने नियमों के अनुसार यथा निर्धारित तुलनात्मक प्रतिनिधि मूल्य, या
- (iv) उप-धारा (6) के अंतर्गत बने नियमों के अनुसार यथा निर्धारित प्रशासनिक बिक्री और सामान्य लागतों एवं लाभों के लिए उचित वृद्धि के साथ उद्गम के देश में उक्त वस्तु के उत्पादन की लागत ।

"वशत कि एस मामले में जहां वस्तु का आयात उद्गम वाले देश से इतर किसी देश से किया गया है तथा जहां वस्तु का निर्यात वाला देश से होकर केवल वाहनान्तरित किया गया है या ऐसी वस्तु का निर्यात वाला देश में उत्पादन नहीं किया जाता है या निर्यात वाले देश में कोई भी तुलनात्मक कीमत नहीं है तब सामान्य मूल्य का निर्धारण उद्गम वाले देश में इसकी कीमत के संदर्भ में किया जाएगा ।"

- (v) प्राधिकारी ने उपरोक्त धारा के अनुसार संबद्ध देशों के निर्यातकों को जांच से संगत सूचना प्रस्तुत करने और टिप्पणियां, यदि कोई हो, प्रस्तुत करने का अवसर प्रदान किया। प्राधिकारी ने भारत में संबद्ध देशों के दूतावासों को भी लिखा।

11. यूरोपीय संघ का क्षेत्र

(क) सामान्य मूल्य

प्राधिकारी नोट करते हैं कि यूरोपीय संघ के क्षेत्र के किसी भी निर्यातक/उत्पादक ने निर्धारित प्रश्नावली के अनुसार सूचना प्रस्तुत नहीं की है। तथापि, मै0 बेयर, जर्मनी ने टिप्पणियां प्रस्तुत की हैं जिन पर ऊपर विचार किया गया है।

सामान्य मूल्य का निर्धारण याचिकाकर्ता द्वारा यथा-प्रदत्त पॉली-आइसा-बुटालिन की परिकल्पित उत्पादन लागत के आधार पर जांच शुरूआत के समय किया गया था। प्राधिकारी ने प्रारंभिक निर्धारण के लिए उस स्वीकार किया है। तदनुसार, यूरोपीय संघ क्षेत्र के सभी निर्यातकों के लिए पॉली-आइसा-बुटालिन का सामान्य मूल्य XXX अमरीकी डॉलर/एम टी लिया गया है।

(ख) निर्यात कीमत

यूरोपीय संघ के क्षेत्र के किसी भी निर्यातक ने प्रश्नावली के उत्तर में निर्यात कीमत के ब्यौरे प्रस्तुत नहीं किए हैं। प्राधिकारी ने डी जी सी आई एड एस, कलकत्ता के आंकड़ों के आधार पर निर्यात कीमत को स्वीकार किया है। याचिकाकर्ता के दावे के आधार पर समुद्री भाड़े, बीमा,

स्वदेशी भाड़े, पत्तन प्रभारों और कमीशन पर क्रमशः ***.***.***.*** और *** डालर/एम टी तक विचार किया गया है। इस प्रकार, जांच अवधि में कारखानागत निर्यात कीमत **** डालर/एम टी निकलती है।

12. ब्राजील

(क) सामान्य मूल्य

प्राधिकारी नोट करते हैं कि ब्राजील के किसी भी निर्यातक/उत्पादक ने निर्धारित प्रश्नावली के अनुसार सूचना प्रदान नहीं की है।

सामान्य मूल्य का निर्धारण याचिकाकर्ता द्वारा यथा-प्रदत्त पोली-आइसो-बुटालिन की परिकल्पित उत्पादन लागत के आधार पर जांच शुरूआत के समय किया गया था। प्राधिकारी ने प्रारंभिक निर्धारण के लिए उसे स्वीकार किया है। तदनुसार, ब्राजील के सभी निर्यातकों के लिए पोली-आइसो-बुटालिन का सामान्य मूल्य xxx अमरीकी डालर/एम टी लिया गया है।

(ख) निर्यात कीमत

ब्राजील के किसी भी निर्यातक ने प्रश्नावली के उत्तर में निर्यात कीमत के ब्यौरे प्रस्तुत नहीं किए हैं। प्राधिकारी ने डी जी सी आई एंड एम, कलकत्ता के आंकड़ों के आधार पर निर्यात कीमत को स्वीकार किया है। याचिकाकर्ता के दावे के आधार पर समुद्री भाड़ा, बीमा, स्वदेशी भाड़ा, पत्तन प्रभारों और कमीशन पर क्रमशः ***.***.***.*** और *** डालर/एम टी तक विचार

किया गया है। इस प्रकार, जांच अवधि में कारखानागत निर्यात कीमत **** डालर/एम टी निकलती है।

13. जापान

(क) सामान्य मूल्य

प्राधिकारी नोट करते हैं कि जापान के किसी भी निर्यातक/उत्पादक ने निर्धारित प्रश्नावली के अनुसार सूचना प्रदान नहीं की है। जांच की शुरुआत के समय सामान्य मूल्य का निर्धारण पाली-आइसो-बुटालिन की परिकल्पित उत्पादन लागत जैसा कि याचिकाकर्ता द्वारा उपलब्ध करवाई गई थी, के आधार पर किया गया था। प्राधिकारी इसी का ही प्रारंभिक निर्धारण के लिए अपनाते हैं। तदनुसार, जापान से हुए सभी निर्यातों के लिए पाली-आइसो-बुटालिन का सामान्य मूल्य *** अमरीकी डालर प्रति मी.टन लिया गया है।

(ख) निर्यात कीमत

प्रश्नावली के उत्तर में जापान से किसी भी निर्यातक ने निर्यात कीमत के ब्यौर प्रस्तुत नहीं किए हैं। याचिकाकर्ता के दाव के आधार पर प्राधिकारी ने मै0 इंडियन ऑयल कारपोरेशन का जापान के निर्यातको द्वारा प्रस्तावित कीमतों तथा जांच की अवधि के लिए डी जी सी आई एंड एस, कलकत्ता के निर्यात आंकड़ों के आधार पर भारित औसत निर्यात कीमत का निर्धारण किया है। प्राधिकारी ने याचिकाकर्ता के दाव के आधार पर ***, ***, ***, *** तथा *** डालर/मी टन

की सीमा तक क्रमशः समुद्री भाड़े, बीमा, स्वदशी भाड़े, पत्तन प्रभारों और कमीशन को माना है ।

अतः जांच की अवधि में कारखाना द्वारा पर निर्यात कीमत *** डालर/मी.टन बनती है ।

14. कोरिया जनवादी गणराज्य

मै0 डेलिम कारपोरेशन, सिओल, कोरिया

(क) सामान्य मूल्य

प्राधिकारी यह नोट करते हैं कि निर्यातक/उत्पादक ने निर्धारित प्रश्नावली के अनुसार अपेक्षित सूचना उपलब्ध करवाई है । निर्यातक ने जांच की अवधि के दौरान कोरिया जनवादी गणराज्य में संबद्ध वस्तु की बिक्रियों के बीजकवार ब्यौरे उपलब्ध करवाए हैं । निर्यातकों द्वारा दावा की गयी उत्पादन लागत के ब्यौरे के आधार पर घरेलू बाजारों में बिक्रियाँ उत्पादन लागत से अधिक कीमत पर हुई हैं और इसलिए प्रारंभिक जांच परिणाम के उद्देश्य से उन्हें व्यापार के सामान्य स्वरूप में माना जाता है । सत्यापन के अधीन रहते हुए प्राधिकारी ने निर्यातक/उत्पादक द्वारा यथा इंगित समायोजन पर भी विचार किया है । जांच की अवधि में भारत औसत कारखाना द्वारा पर घरेलू बिक्री कीमत *** अमरीकी डालर/मी.टन बैठती है ।

(ख) निर्यात कीमत

प्राधिकारी यह नाट करते हैं कि निर्यातक/उत्पादक ने जांच की अवधि के दौरान संबद्ध वस्तु की भारत का हुई निर्यात बिक्रियों के सौदवार ब्यौरे उपलब्ध करवाए हैं । निर्यातक/उत्पादक ने

भारत को निर्यात के लिए बिक्री कीमत ढाच म निर्यात कीमत के विभिन्न समायोजनों अर्थात् छूट/कमीशन, पैकिंग, स्वदेशी भाड़ा, समुद्री भाड़ा, नौवहन प्रभारों इत्यादि का दर्शाया है । प्रारंभिक जांच परिणाम के उद्देश्य से प्राधिकारी ने निर्यातक/उत्पादक द्वारा दर्शाए गए समायोजनों पर विचार करते हैं । भारत के लिए संबद्ध वस्तु की भारत औसत कारखाना द्वार पर निर्यात कीमत *** डालर/मी.टन बनती है ।

15. कोरिया गणराज्य के अन्य निर्यातक/उत्पादक

(क) सामान्य मूल्य

चूँकि कोरिया गणराज्य के किसी अन्य निर्यातक/उत्पादक ने सूचना उपलब्ध नहीं करवाई है इसलिए प्राधिकारी ने सामान्य मूल्य का आकलन करने के लिए अन्य सहयोगी निर्यातक द्वारा दर्शायी गयी भारत औसत घरेलू बिक्री कीमत का स्वीकार किया है । जांच की अवधि के दौरान संबद्ध वस्तु के लिए कोरिया गणराज्य के अन्य निर्यातक/उत्पादक के मामले में सामान्य मूल्य *** डालर/मी टन बनता है ।

(ख) निर्यात कीमत

प्राधिकारी ने समुद्री भाड़ा, बीमा, कमीशन इत्यादि के संबंध में किसी समायोजन के बिना कोरिया गणराज्य के सहयोगी निर्यातक द्वारा उपलब्ध करवाए गए अनुसार भारत के लिए न्यूनतम निर्यात कीमत *** अमरीकी डालर/मी.टन स्वीकार की है ।

16. सिंगापुर**(क) सामान्य मूल्य**

प्राधिकारी यह नाट करते हैं कि सिंगापुर क किसी भी निर्यातक/उत्पादक न निर्धारित प्रश्नावली क अनुसार सूचना उपलब्ध नहीं करवाई है ।

जांच की शुरुआत क समय सामान्य मूल्य का निर्धारण याचिकाकर्ता द्वारा उपलब्ध करवायी गयी पाली-आइसा-बुटालिन की परिकल्पित उत्पादन लागत क आधार पर किया गया था । प्राधिकारी इस प्रारंभिक निर्धारण क प्रयोजनाथ स्वीकार करते हैं । तदनुसार, सिंगापुर क सभी निर्यातकों क लिए पाली-आइसा-बुटालिन का सामान्य मूल्य ***** अमरीकी डालर/मी.टन लिया गया है ।

(ख) निर्यात कीमत

सिंगापुर क किसी भी निर्यातक न प्रश्नावली क उत्तर में निर्यात कीमत क ब्यौरे प्रस्तुत नहीं किए है । याचिकाकर्ता क दाव क आधार पर प्राधिकारी न मै0 इंडियन ऑयल कारपोरेशन का सिंगापुर क निर्यातकों द्वारा प्रस्तावित कीमतों तथा जांच की अवधि क लिए डी जी सी आई एड एम्, कलकत्ता क निर्यात आकड़ों क आधार पर भारत आसत निर्यात कीमत का निर्धारण किया है ।

17. थाईलैंड**(क) सामान्य मूल्य**

प्राधिकारी यह नाट करते हैं कि थाईलैंड स किसी भी निर्यातक/उत्पादक न निर्धारित प्रश्नावली क अनुसार सूचना उपलब्ध नहीं करवायी है ।

जांच की शुरुआत के समय सामान्य मूल्य का निर्धारण याचिकाकर्ता द्वारा उपलब्ध करवायी गयी पोली-आइसो-बुटालिन की परिकल्पित उत्पादन लागत के आधार पर किया गया था । प्राधिकारी प्रारंभिक निर्धारण के लिए इसे ही स्वीकार करते हैं । तदनुसार, थाइलैंड के सभी निर्यातकों के लिए पोली-आइसो-बुटालिन का सामान्य मूल्य **** अमरीकी डालर/मी.टन लिया गया है ।

(ख) निर्यात कीमत

थाइलैंड के किसी भी निर्यातक ने प्रश्नावली के उत्तर में निर्यात कीमत के ब्यौरे प्रस्तुत नहीं किए हैं । प्राधिकारी ने निर्यात कीमत डी जी सी आई एण्ड एस, कलकत्ता के आंकड़ों के आधार पर स्वीकार की है ।

प्राधिकारी ने याचिकाकर्ता के दावे के आधार पर ****, ****, **** तथा **** डालर/मी.टन तक क्रमशः समुद्री भाड़े, बीमा, स्वदेशी भाड़ा, पत्तन प्रभारों और कमीशन का स्वीकार किया है । अतः जांच की अवधि में कारखाना द्वार पर निर्यात कीमत *** डालर/मी.टन बनती है।

(ग) पाटन - सामान्य मूल्य तथा निर्यात कीमत की तुलना

18. तुलना से संबंधित नियमों में निम्नलिखित प्रावधान है -

"पाटन का मार्जिन निकालते समय निर्दिष्ट प्राधिकारी निर्यात कीमत और सामान्य मूल्य के बीच एक उचित तुलना करेगा । यह तुलना व्यापार के एक समान स्तर पर सामान्यतया कारखाना

द्वार स्तर पर की जाएगी और यथा संभव उसी समयवाधि के दौरान की गयी बिक्रियों के सबध में की जाएगी । जा अंतर कीमत तुलनीयता पर प्रभाव डालते हैं, उनके लिए प्रत्येक मामले में गुण-दोष के आधार पर उचित छूट दी जाएगी । उक्त अंतर में बिक्री की शर्तें, कराधान, व्यापार के स्तर, मात्राएं, भौतिक विशेषताएं तथा अन्य ऐसे अंतर शामिल हैं, जा कीमत तुलनीयता का प्रभावित करने के लिए प्रदर्शित किए जाते हैं ।"

प्राधिकारी ने पाटन मार्जिन के मूल्यांकन के लिए भारत औरसत सामान्य मूल्य की भारत औरसत कारखानागत निर्यात कीमत से तुलना की है ।

संबद्ध दश में संबद्ध वस्तु के उत्पादक/निर्यातक के लिए पाटन मार्जिन निम्नानुसार है:-

देशवार निर्यातक/उत्पादक	सामान्य मूल्य (डालर/मी.टन)	निर्यात कीमत (डालर/मी.टन)	पाटन मार्जिन (%)
कोरिया जनवादी गणराज्य			
(i) मै0 डेलिम कारपारेशन लि0	***	***	15.72 %
(ii) अन्य सभी निर्यातक/उत्पादक	***	***	46.29 %
सभी निर्यातक/उत्पादक			
(i) यूरोपीय संघ	***	***	18.03 %
(ii) ब्राजील	***	***	44.63 %
(iii) जापान	***	***	57.23 %
(iv) थाइलैंड	***	***	19.09 %
(v) सिंगापुर	***	***	34.36 %

उपरोक्त पाटन मार्जिन न्यूनतम सीमा से अधिक है ।

क्षति

19 उपराक्त नियम 11, अनुबंध-II के तहत जब क्षति के बारे में किसी निष्कर्ष पर पहुँचा जाता है तो इस प्रकार के निष्कर्ष में " पाटित आयातों की मात्रा, घरेलू बाजार में समान वस्तुओं की कीमती पर उनका प्रभाव तथा इस प्रकार की वस्तुओं के घरेलू उत्पादकों पर ऐसे आयातों के परिणामी प्रभाव सहित सभी सगत तथ्यों पर विचार करते हुए घरेलू उद्योग का हुई क्षति का निर्धारण शामिल होगा " कीमती पर पाटित आयातों के प्रभाव पर विचार करते समय यह जांच करना आवश्यक समझा जाता है कि पाटित आयातों के कारण भारत में समान वस्तुओं की कीमत की तुलना में कोई उल्लेखनीय गिरावट आई है अथवा नहीं अथवा क्या इस प्रकार के आयातों से कीमत में कोई अन्यथा उल्लेखनीय स्तर तक गिरावट आयी है, अथवा कीमत वृद्धि में अन्यथा रूकावट आयी है जा कि अन्यथा उल्लेखनीय स्तर तक बढ़ गई होती ।

भारत में घरेलू उद्योग पर आयातों के प्रभाव की जांच करने के लिए उक्त नियमावली के अनुबंध-II(iv) के अनुसरण में ऐसे संकेतकों पर विचार किया गया है जो उद्योग की स्थिति पर प्रभाव डालते हैं जैसे उत्पादन, क्षमता का उपयोग, बिक्री की मात्रा, भंडार, लाभप्रदता, निवल बिक्री प्राप्ति, पाटन की मात्रा और मार्जिन इत्यादि ।

ट. क्षति का संचयी मूल्यांकन

20. नियमावली के अनुबंध-II के नियम (III) के अनुसार यह अपेक्षित है कि एक से अधिक दशों से किसी उत्पाद के आयातों के मामले में जब पाटनरोधी जांच एक साथ की जा रही है तो

प्राधिकारी इस प्रकार के आयातों का संचयी रूप से आकलन करेगा। तथापि, इस प्रकार का आकलन तभी किया जा सकता है जब यह निर्धारित हो जाए कि प्रत्येक देश से आयातों के संबंध में पाटन मार्जिन निर्यात कीमत के प्रतिशत के रूप में व्यक्त 2 प्रतिशत से अधिक है और प्रत्येक देश से हुए आयातों की मात्रा भारत में समान वस्तु के आयात का 3 प्रतिशत है अथवा जहां प्रत्येक देश का निर्यात 3 प्रतिशत से कम है वहां संचयी रूप से आयात समान वस्तु के आयातों का 7 प्रतिशत से अधिक बनता है, और आयातों के प्रभाव का संचयी आकलन, आयातित वस्तु तथा समान घरेलू वस्तु के बीच प्रतिस्पर्धा की स्थितियों की दृष्टि से उचित है।

प्राधिकारी नाट करत है कि पाटन मार्जिन तथा संबंधित देश से हुए आयातों की मात्रा ऊपर निर्धारित सीमाओं से अधिक है। यूरोपीय संघ, ब्राजील, जापान, कोरिया जनवादी गणराज्य, सिंगापुर और थाइलैंड के आयातों के प्रभाव का संचयी आकलन उचित है क्योंकि इन देशों की निर्यात कीमत भारतीय बाजार में घरेलू उद्योग द्वारा दी गयी कीमतों से प्रत्यक्ष रूप से प्रतिस्पर्धा कर रही हैं और यहाँ घरेलू उत्पादकों का विस्थापित कर रही हैं।

21. ऊपर यथा उल्लिखित घरेलू उद्योग का प्रभावित करने वाले सभी मापदण्डों जैसे कि उत्पादन, क्षमता उपयोग, बिक्री मात्रा इत्यादि की निम्नानुसार जांच की गयी है:

(क) आयातों की मात्रा और बाजार:

पोली-आइसा-बुटालिन के आयातों की मात्रा के संबंध में सूचना डी जे सी आइ एंड एस कलकत्ता द्वारा प्रकाशित सूचना पर आधारित है। प्राधिकारी नाट करत हैं कि 1999-2000 के दौरान संबंधित देशों से संबंधित वस्तु के आयातों का बाजार हिस्सा संचयी रूप से 73.60 % था। जांच अवधि के दौरान यह बढ़कर 86.62 % हो गया। जांच की अवधि के दौरान कुल आयात में 1999-00 की तुलना में 13 % वृद्धि हुई है।

(ख) उत्पादन

वर्ष 1999-00 के दौरान सबद्ध वस्तु का याचिकाकर्ता कंपनी का कुल उत्पादन 6111 मी.टन था जो जांच अवधि के दौरान गिरकर 5648 मी.टन (वार्षिक आधार पर) हो गया जो लगभग 7.58 % की गिरावट दर्ज करता है।

(ग) बिक्री मात्रा

वर्ष 1999-00 के दौरान याचिकाकर्ता कंपनी की कुल बिक्री मात्रा 6392 मी.टन थी जो जांच अवधि के दौरान गिरकर 5217 मी.टन (वार्षिक आधार पर) हो गया जो लगभग 18.38 % की गिरावट दर्शाती है।

(घ) क्षमता उपयोग

याचिकाकर्ता ने वर्ष 1999-00 में 81.48 % का औसत क्षमता उपयोग प्राप्त किया था जो जांच की अवधि के दौरान गिरकर 75.31 % हो गया।

(ड) बिक्री वसूली

वर्ष 1999-00 के दौरान विभिन्न घरेलू बाजार में सबद्ध वस्तु की बिक्री में याचिकाकर्ता कंपनियाँ की औसत बिक्री वसूली XXXX रूपए प्रति मी.टन थी जो 2000-01 में बढ़कर XXXX रूपए प्रति मी.टन हो गयी और यह 5.26 % की वृद्धि प्रदर्शित करती है। तथापि, जांच अवधि के अंतिम पांच महीनों के दौरान औसत बिक्री वसूली गिरकर XXXX रूपए हो गयी इससे जांच की अवधि में ही घरेलू बिक्री वसूली में भारी गिरावट दिखाई देती है। तथापि, आगे यह भी देखा गया है कि सबद्ध वस्तु के उत्पादन की औसत लागत जांच की अवधि के दौरान 1999-00 की तुलना में XXXX रूपए प्रति मी.टन तक बढ़ गई। तदनुसार जांच की अवधि के दौरान बिक्री वसूली में वृद्धि से इसी अवधि के दौरान पिछले वर्ष की तुलना में उत्पादन लागत में हुयी वृद्धि की क्षतिपूर्ति नहीं हुई है।

(च) लाभप्रदता

यह पाया गया है कि वर्ष 1999-00 के दौरान याचिकाकर्ता संबद्ध वस्तु का **** रूपए प्रति मी.टन का निबल लाभ कमा रहा था । तथापि, जांच अवधि के दौरान याचिकाकर्ता का संबद्ध वस्तु से **** रूपए प्रति मी.टन का घाटा हुआ ।

.(छ) गवाई गई संविदा का साक्ष्य

मै0 इंडियन ऑयल कारपोरेशन द्वारा जारी की गयी निविदा में निर्यातकों द्वारा उद्धृत की गयी कम कीमतों से घरेलू उद्योग संविदाएं गंवाएंगी । उस एकमात्र निविदा जिसमें याचिकाकर्ता न न्यूनतम कीमतें उद्धृत की हैं, से भी घरेलू उद्योग को काफी घाटा होगा ।

(ज) अन्तिम स्टॉक

वर्ष 1999-2000 की तुलना में जांच अवधि के दौरान घरेलू उद्योग का अंतिम स्टॉक **** मी.टन से पर्याप्ततः बढ़कर **** मी टन हो गया जो 351 प्रतिशत की वृद्धि प्रदर्शित करता है ।

(ठ) कारणात्मक संबंध

22(क) प्राधिकारी घरेलू उद्योग की उत्पादन लागत और संबद्ध देशों से निर्यातों की पहुँच मूल्य की सावधानी पूर्वक जांच करने के पश्चात यह नाट करत हैं कि यूरोपीय संघ (इ यू) के क्षेत्र और थाइलैंड के मामले में जांच अवधि के दौरान निर्यातों का औसत पहुँच मूल्य घरेलू उद्योग के लिए

निकाली गयी क्षति रहित कीमत से अधिक है तदनुसार इन दशा से हुए निर्यातों और घरलू उद्योग का हुई वास्तविक क्षति के बीच कोई कारणात्मक संबंध स्थापित नहीं होता है । प्राधिकारी नाट करत है कि शेष दशा से अर्थात् ब्राजील, जापान, कारिगा गणराज्य और सिंगापुर से भारत का पाली-आइरा-ब्यूटामी का निर्यात इसक सामान्य मूल्य पर कम कीमत पर किया गया है ।

(ख) डी जी सी आई एण्ड एस द्वारा यथा-संचित और इंडियन ऑयल कारपोरेशन द्वारा जारी की गई निवेदा में यथा उद्धृत भाव के अनुसार संबद्ध दशा से निर्यात की औसत कीमत में अमरीकी डालर के रूप में पर्याप्त गिरावट आयी है । याचिकाकर्ता कंपनी का जांच अवधि के दौरान उत्पादन लागत में वृद्धि होने के बावजूद बिक्री कीमत में कमी करनी पड़ी । याचिकाकर्ता कंपनी पहले संबद्ध वस्तु की बिक्री लाभ पर कर रही थी । जांच अवधि के दौरान इसी वस्तु का घरलू बाजार में भारी घाटे पर ही बच सकी ।

य सभी मापदण्ड सचर्या रूप से प्रदर्शित करत हैं कि याचिकाकर्ता कंपनी का वास्तविक क्षति हुई है और याचिकाकर्ता कंपनी का यह क्षति संबद्ध वस्तु के पाटित आयातों के कारण हुई है ।

(ड) भारतीय उद्योग के हित और अन्य मुद्दे

23(क) सामान्य तौर पर पाटनराधी शुल्क लगाने का उद्देश्य एस पाटन का समाप्त करना है जिससे भारतीय उद्योग का नुकसान हो रहा है तथा भारतीय बाजार ^{में} एसी खुली और उचित प्रतिस्पर्धा की पुनः स्थिति लाना है जो कि देश के सामान्य हित में है ।

(ख) प्राधिकारी यह मानते हैं कि पाटनरोधी शुल्क लगाने से संबद्ध वस्तुओं के उपयोग से विनिर्मित उत्पादों की कीमत स्तर प्रभावित होगी और परिणामस्वरूप इन उत्पादों की तुलनात्मक प्रतिस्पर्धात्मकता पर कुछ प्रभाव पड़ सकता है किन्तु, पाटनरोधी उपायों से भारतीय बाजार में उचित प्रतिस्पर्धा कम नहीं होगी, विशेषकर तब जब पाटनरोधी शुल्क की लवी उस राशि तक ही सीमित कर दी जाए जो कि याचिकाकर्ता कंपनी को हुए नुकसान को कम करने के लिए आवश्यक है। इसके विपरीत, पाटनरोधी उपायों को लागू करने से पाटन द्वारा प्राप्त हुए अनुचित लाभ समाप्त होंगे। याचिकाकर्ता कंपनियों के ह्रास को रोका जा सकता है और इस प्रकार पाली-आइसा-ब्राजील के उपभोक्ताओं के लिए व्यापक विकल्प उपलब्ध कराने में मदद मिलेगी। पाटनरोधी उपायों से संबद्ध देशों से आयात किसी भी प्रकार कम नहीं होगी, इसलिए उपभोक्ताओं के लिए उत्पादों की उपलब्धता पर कोई असर नहीं पड़ेगा।

(ढ) निष्कर्ष

24. पूर्वोक्त पर विचार करने के पश्चात् यह देखा जा सकता है कि:

- (क) संबद्ध देशों के मूल के अथवा वहां से निर्यातित पाली-आइसा-ब्राजील का भारत को निर्यात सामान्य मूल्य से कम कीमत पर किया गया है जिसके कारण पाटन हुआ है
- (ख) भारतीय उद्योग को केवल ब्राजील, जापान, कोरिया गणराज्य और सिंगापुर से हुए संबद्ध वस्तु के निर्यात से वास्तविक क्षति हुई है
- (ग) यह क्षति सचयी रूप से ब्राजील, जापान, कोरिया गणराज्य और सिंगापुर से हुए आयातों के कारण हुई है।

25. यह आवश्यक समझा गया है कि अंतिम निर्धारण होने तक ब्राजील, जापान, कोरिया गणराज्य और सिंगापुर के मूल के अथवा वहां से निर्यातित पाली-आइसो-प्रोपाइनिक सभी आयातों पर अनन्तिम पाटनरोधी शुल्क लगाया जाए।

26. इस बात पर विचार किया गया था कि क्या पाटन मार्जिन से कम पाटनरोधी शुल्क की राशि लगाना क्षति का समाप्त करने के लिए पर्याप्त होगा। इस उद्देश्य के लिए आयातों की औसत पहुंच कीमत की तुलना जांच अवधि के लिए निर्धारित याचिकाकर्ता कंपनी की क्षति रहित कीमत के साथ की गयी थी। जहां अंतर पाटन मार्जिन से कम रहा था वहां पाटन मार्जिन से कम शुल्क लगाने की सिफारिश की जाती है। तदनुसार, यह प्रस्ताव किया जाता है कि अंतिम निर्धारण होने तक सीमाशुल्क टैरिफ अधिनियम 1975 के अध्याय 29 या किसी दूसरे अध्याय के अंतर्गत आने वाले ब्राजील, जापान, कोरिया गणराज्य और सिंगापुर के मूल के अथवा वहां से निर्यातित संबद्ध वस्तु के सभी ग्रेडों पर कन्द्र सरकार द्वारा इस संबंध में जारी की जाने वाली अधिसूचना की तिथि से नीचे कॉलम दो में दी गयी राशि और आयातों के पहुंच मूल्य के बीच के अंतर को राशि के बराबर का अनन्तिम पाटनरोधी शुल्क लगाए जाए।

देशवार निर्यातक/उत्पादक (1)	राशि अमरीकी डॉलर प्रति मी.टन (2)
कोरिया गणराज्य	
(i) मै0 डोलिम कारपोरेशन लि0	1037.77
(ii) अन्य सभी निर्यातक/उत्पादक	1037.77
निम्नलिखित देशों के सभी निर्यातक/उत्पादक	
(i) यूरोपीय संघ का क्षेत्र	लागू नहीं
(ii) ब्राजील	1037.77
(iii) जापान	1037.77
(iv) थाईलैंड	लागू नहीं
(v) सिंगापुर	1037.77

27 इस उद्देश्य के लिए आयातों का पहुँच मूल्य सीमाशुल्क अधिनियम 1975 की धारा 3-3 के
 8 ख, 9 और 9-क के तहत लगाए गए अतिरिक्त शुल्कों को छोड़कर सीमाशुल्क अधिनियम 1962
 के अधीन सीमाशुल्क द्वारा यथा आकलित निवारणीय मूल्य हानों और उसमें सभी प्रकार के
 सीमाशुल्क शामिल होंगे ।

(ण) आगे की प्रक्रिया

28 प्रारम्भिक जांच परिणामों का अधिसूचित करने के बाद निम्नलिखित प्रक्रिया का पालन किया
 जाएगा -

- (क) प्राधिकारी सभी हितबद्ध पार्टियों से इन जांच परिणामों के बारे में टिप्पणियाँ आमंत्रित करेंगे
 और उन पर अंतिम जांच परिणामों में विचार किया जाएगा,
- (ख) प्राधिकारी द्वारा निर्यातकों, आयातकों, प्राधिकारकर्ता तथा अन्य हितबद्ध पार्टियों का अलग से
 लिखा जा रहा है जा पत्र की प्रेषण की तारीख से 40 दिनों के भीतर अपने विचार प्रस्तुत
 कर सकते हैं । कोई अन्य हितबद्ध पार्टी भी इन जांच परिणामों के प्रकाशन की तारीख से
 40 दिनों के भीतर अपने विचारों से अवगत करा सकती है ।
- (ग) प्राधिकारी आवश्यक समझी गयी सीमा तक आगे जांच करेंगे ।
- (घ) अंतिम जांच परिणामों की घोषणा से पहले प्राधिकारी आवश्यक तथ्यों का प्रकटन करेंगे ।

एल.बी. सप्तऋषि, निर्दिष्ट प्राधिकारी

MINISTRY OF COMMERCE AND INDUSTRY**(Department of Commerce)****NOTIFICATION**

New Delhi, the 12th December, 2001

Subject :—Anti-Dumping Duties concerning imports into India by Poly-Iso-Butylene originating in or exported from European Union, Brazil, Japan, Korea RP, Singapore and Thailand—Preliminary Findings

No. 47/1/2001-DGAD.—Having regard to the Customs Tariff Act 1975 as amended in 1995 and the Customs Tariff (Identification, Assessment and Collection of Anti-Dumping Duty on Dumped Articles and for Determination of Injury) Rules, 1995, thereof

A. PROCEDURE:

1. The procedure described below has been followed with regard to the investigations:-
 - (i) The Designated Authority (hereinafter referred to as Authority), under Rules, received written application from M/s. Kothari Sugars & Chemicals Limited, Manali, Chennai alleging dumping of Poly-Iso-Butylene (hereinafter referred to as subject goods), originating in or exported from European Union, Brazil, Japan, Korea RP, Singapore and Thailand (hereinafter referred to as subject countries).
 - (ii) The Authority, on the basis of sufficient evidence submitted by the petitioner, decided to initiate investigations against imports of Poly-Iso-Butylene from the subject countries. The Authority notified the Embassies/High Commissions of subject countries about the receipt of dumping allegation before proceeding to initiate investigations in accordance with sub-rule 5(5) of the Rules;
 - (iii) The Authority issued a Public Notice dated the 12th September, 2001, published in the Gazette of India, Extraordinary, initiating Anti-Dumping investigations concerning imports of Poly-Iso-Butylene originating in or exported from the subject countries, classified under Custom sub-headings 3902.20 under Chapter 39 of the Customs Tariff Act, 1975.
 - (iv) The Authority forwarded a copy of the Public Notice to the known exporters (whose details were made available by the petitioners) and industry associations and gave them an opportunity to make their views known in writing in accordance with Rule 6(2);
 - (v) The Authority forwarded a copy of the Public Notice to the known importers of subject goods in India (whose details were made available by the petitioners) and advised them to make their views known in writing within forty days from the date of the letter;
 - (vi) Request was made to the Central Board of Excise and Customs (CBEC) to arrange details of imports of subject goods for the past three years, including the period of investigations;

- (vii) The Authority provided a copy of the petition to known exporters and the Embassies/High Commissions of the subject countries in accordance with Rule 6(3) supra.
- (viii) The Authority sent questionnaire, to elicit relevant information, to the known exporters from subject countries as mentioned below in accordance with the rule 6(4):-
- ◆ M/s BP Chemicals Ltd., Scotland.
 - ◆ M/s DAELIM Corporation, Seoul, Korea.
 - ◆ M/s Exxon Chemical Companies, New Jersey, USA.
 - ◆ M/s Idemitsu Petrochemicals Corporation Limited, Japan.
 - ◆ M/s BP Chemicals SNC, Paris La Defense.
 - ◆ M/s Exxon Chemical, Singapore.
 - ◆ M/s BASF, Germany.
 - ◆ M/s Exxon Mobil Singapore Pte. Ltd., Singapore.

The response was, however, filed by the following exporters of subject goods:

- ◆ M/s BASF, Germany.
 - ◆ M/s DAELIM Corporation, Seoul, Korea.
- (ix) The Embassies/High Commissions of the subject countries in New Delhi were informed about the initiation of the investigations in accordance with Rule 6(2) with a request to advise the exporters/producers from their country to respond to the questionnaire within the prescribed time. A copy of the letter, petition and questionnaire sent to the exporter was also sent to the Embassies/High Commissions of subject countries along with a list of known exporters/ producers.
- (x) A questionnaire was sent to the following known importers and Consumers of subject goods in India calling for necessary information in accordance with Rule 6(4):-

Contd. 3/-

- ◆ M/s. Bharat Sheet Limited, Maharashtra.
- ◆ M/s. Gulf Oil India Limited Dadara Nagar Haveli.
- ◆ M/s. Bharat Petroleum Corporation Limited, Mumbai.
- ◆ M/s. IBP Company Limited, Calcutta.
- ◆ M/s. Indian Additives Limited, Manali, Chennai.
- ◆ M/s. Lubrizol India Limited, Thane
- ◆ M/s. Hindustan Petroleum Corporation Limited, West Bengal.
- ◆ M/s. Castrol India Limited, Mumbai
- ◆ M/s. Pennzoil Quaker State India Limited, Navi Mumbai.
- ◆ M/s. Maharashtra Polybutenes Limited, Navi Mumbai.
- ◆ M/s. Gujarat Polysynthese Limited, Vadodara.
- ◆ M/s. Cochin Refinery Balmer Lawrie Limited, Kerala.
- ◆ M/s. Indian Oil Corporation Limited, Mumbai.

The response was, however, filed by the following importers / consumers of subject goods:

- ◆ M/s. Lubrizol India Limited, Thane.
- ◆ M/s. Indian Additives Limited, Manali, Chennai.

- (xi) Additional information regarding injury parameters including cost of production was sought from the petitioner, which was also received;
- (xii) The Authority made available non-confidential version of the evidence presented by various interested parties in the form of a public file kept open for inspection by the interested parties;
- (xiii) Optimum cost of production and cost to make and sell the subject goods in India based on the information furnished by the petitioner on the basis of Generally Accepted Accounting Principles(GAAP) was worked out so as to ascertain if Anti-Dumping duty lower than the dumping margin would be sufficient to remove injury to Domestic Industry;
- (xiv) **** in this Notification represents information furnished by the petitioner on confidential basis and so considered by Authority under the Rules;
- (xvi) Investigation was carried out for the period starting from 1st April, 2000 to 31st August, 2001.

B. PETITIONER'S VIEWS:

2. The petitioners have raised the following issues:-

- (a) The imports of Poly-Iso-Butylene from the subject countries have increased significantly in absolute terms. The volume of imports in the current year by Indian Oil Corporation Ltd. alone would be 2700 MTs considering the prices quoted by the exporters;
- (b) The export price from the subject countries have declined significantly. Further decline in export price in US\$(which is more relevant for the exporters) is much more significant than Indian Rupees. M/s. Indian Oil Corporation Ltd. has recently floated International tender for procurement of the product at three places in India, viz. Trombay, Chennai and Calcutta. The prices quoted by these exporters in these tenders are at significantly reduced levels which cannot permit recovery of cost of production for any producer of the product in these countries.
- (c) The selling price of the Domestic Industry which was increasing till 2000-01 reduced significantly in 2001-02. Moreover increase in the selling price in 2000-01 over 1999-2000 was much lower than increase in the cost of production resulting in significant financial losses to the Domestic Industry.

- (d) The dumped imports are causing severe price undercutting to the Domestic Industry in the market. The price which exporter have quoted recently in the tender do not permit recovery of even cost of production, leave alone profit. The quotations by the exporters have resulted in severe price suppression/ depression in the Indian market. The Domestic Industry would loss substantial sales given the price quoted by the exporters in the recently floated tenders.
- (e) The Domestic Industry has been forced to reduce the prices below the cost of production as a result of significant dumping in the country. The financial situation of the Domestic Industry has deteriorated significantly. The Domestic Industry has been forced to a situation of significant financial losses from a situation of profit.

C. **VIEWS OF EXPORTERS, IMPORTERS AND OTHER INTERESTED PARTIES:**

3. **EXPORTERS' VIEWS**

(I) **M/S. BASF AKTIENGESELLSCHAFT, GERMANY:**

M/s. BASF Aktiengesellschaft, Germany has submitted that the product produced by the complainant is not a like product in sense of the GATT Anti Dumping Codex. The quality of the BASF product is different and the imported product can not be substituted by the locally produced. This fact will be demonstrated by their customer M/s Indian Additives Limited (ILA), who imports exclusively the BASF product into India. There is a contract between Chevron Oronite and BASF, which makes no price differentiation concerning the final destination. By such a contract dumping is not possible because Chevron Oronite buys for the EU market as well.

(ii) **M/S. DAELIM INDUSTRIAL CO., LTD., KOREA.**

M/s. DAELIM has made the following submissions :-

(a) **ON STANDING OF THE PETITIONER:**

There are four Poly-Iso-Butylene plants in India and the petitioner M/s. Kothari Chemical Ltd. alone does not represent more that 25% of the production of the subject goods and does not have the standing to file the petition.

(b) **ON INJURY:**

- (i) The imports have increased dramatically since the beginning of 2000 even though the import tax is high at the range of 35%. They have the competitive advantage, the economic of scale, and the quality of product and there own Poly-Iso-Butylene technology over the producers of India. The production cost of their Poly-Iso-Butylene is lower than Indian producers so they could get awarding of tender business.

- (ii) Although the petitioner claims that imported goods has caused injury to the domestic industry, Daelim Poly-Iso-Butylene makes a contribution to the protection of Indian Air Pollution and Indian lubricants oil manufacturers including main importers
- (iii) Although NAPTHA price has dramatically increased between 1999 and 2000 fiscal year, Indian domestic and international Poly-Iso-Butylene price has not increased because of supply surplus around the world. Loss of the petitioner was not caused by imported goods as they also suffered from the same situation in the market.

(c) **TARIFF CLASSIFICATION:**

Poly-Iso-Butylene, is classified as 3902.20 and as 3902.90 as well under the Customs Tariff Act., which is the same as Korean HS Code. We always export Poly-Iso-Butylene to foreign country by using 3902.90. Generally the price of Poly-Iso-Butylene is lower than average price of all products of 3902.20 because the price of HRPIB and Semi-Solid PI B is more expensive. Poly-Iso-Butylene under 3902.20 can be divided into three kinds of P IB as follows:

PRODUCTS	Properties
PI B	Liquid, Low Mw
HRPI B	High Reactive P IB
Semi-Solid PIB	Rubbery Phase, High Mw.

The petitioner's claim needs to be confirmed including volume, price and normal value based on imports into European Union in the petition. Our data indicates that export volume to India is 2,267 MT, whereas the petitioner claims just 1,377 MT in the investigation period.

VIEWS OF OTHER INTERESTED PARTIES

M/S INDIAN PETROCHEMICALS CORPORATION LIMITED (IPCL), GUJARAT.

M/s IPCL one of the manufacturers of the subject goods, while supporting the petition have stated that imports of Poly-Iso-Butylene have increased significantly in the past few years. The imports are so low price that at indigenous price of feedstock and conversion cost their margins are at great stress. In the recent tenders floated by Indian Oil Corporation, exporters have quoted significantly lower price, which if they are forced to match, their margins will be eroded to such extent that viability of business will be questionable. The dumping is resulting in significant injury to the Indian industry. The situation demands immediate imposition of anti dumping duty on dumped imports from subject countries.

(ii) **M/S. KOCHI REFINERIES LIMITED:**

M/s. Kochi Refineries Limited, one of the manufacturers of the subject goods in the country, has supported the anti dumping petition filed by M/s. Kothari Sugar and Chemicals Limited. In response to the questionnaire they have submitted the cost details and has made the following submissions:-

- (a) Due to dumping of the product by the foreign agencies on the Indian market they had to reduce their prices, far below the cost of production so as to match the landed price of the imported product to sustain operation of the plant. They had to drastically cut down the price to match with the prices offered by the foreign vendors in the tenders floated by major marketing company in India.
- (b) In the financial year 2000-2001 they made a net loss of about Rs. **** crores against a total turn over of approximately Rs. **** crores. They are selling the subject goods below the total cost of production due to severe market pressures.

5. **VIEWS OF IMPORTERS:**

(i) **M/S. INDIAN ADDITIVES LIMITED, CHENNAI:**

M/s. Indian Additives Limited has submitted that they were using conventional Poly-Iso-Butylene (P IB) until the end of the year 1999. Now they have substituted it with another product HRPIB (highly reactive Poly-Iso-Butylene) due to better economy and quality of manufacture products. Although HRPIB is entirely different in terms of technology, physio chemical property and uses, the customs tariff classification is same as of conventional Poly-Iso-Butylene manufactured by the petitioner company. HRPIB is neither manufactured in India nor any one has the technology. Therefore, they have requested for excluding HRPIB from the purview of the current anti dumping investigation as it is a different product and any way does not affect the indigenous manufacturers including the petitioner company. However the importer has not submitted complete details as per the prescribed Questionnaire.

(ii) **M/S LUBRIZOL INDIA PVT., LTD:**

M/s Lubrizol has intimated that they have not imported the subject goods during the Period of Investigation. However they have stated that they do not support the case of levy of Anti Dumping Duty on Poly-Iso-Butylene for the following reasons:

- (a) There is a surplus capacity available in the international market and the prices internationally are extremely competitive. The present import price of Polybutenes by local consumers is the right competitive international price. Due to large petroleum feed stock becoming surplus due to the shift in the product made/market internationally, the feed stock import to Polybutenes will be further cheaper which will lower the prices over a period.
- (b) One of the largest suppliers of Polybutenes i.e. M/s. Indian Petrochemicals Corporation Ltd. (Govt. of India undertaking) has not come up with such case for anti dumping. When any anti dumping duty is considered by the Government it is voice of the industry that is being looked into but with the overriding fact kept in mind that such actions should not put the consumer/public at disadvantage.

D. **EXAMINATION OF THE ISSUES RAISED:**

- 6. The submissions made by the exporters, importers, petitioner and other interested parties have been examined, considered and have been dealt with at appropriate places hereinafter.

E. **PRODUCT UNDER CONSIDERATION:**

- 7. (a) The product involved in the present petition is Poly-Iso-Butylene also known as PIB or Poly-Iso- Butene (also referred as subject goods hereinafter) originating in or exported from European Union, Brazil, Japan, Korea RP, Singapore and Thailand. Poly-Iso-Butylene is a Synthetic Hydrocarbon Polymer manufactured by polymerisation of C4 Olefins stream consisting mainly Isobutene. Poly-Iso-Butylene finds application in various fields like Lube Oil additives, Cable Filling Compounds, Rubber Modifiers, Leather Chemicals, 2T Oil Formulations, Oil Insulators Adhesives etc. Present investigation covers all forms of Poly-Iso-Butylene.
- (b) Poly-Iso-Butylene is classified under Customs sub heading No. 3902.20 under Chapter 39 of the Customs Tariff Act, 1975.

- (c) The classification is, however, indicative only and is in no way binding on the scope of the present investigation.

F LIKE ARTICLES:

8. Rule 2(d) of the Anti-Dumping Rules specifies that "Like Articles" means an Article which is identical or alike in all respects to the product under investigation or in the absence of such an Article, another article, having characteristics closely resembling those of the articles under examination.

In response to M/s. BASF, Germany's claim that the product exported by them is different from the product produced by the petitioner the Authority holds that HRPB is nothing but Poly Iso Butylene as the product has similar physical and chemical characteristics, product specification, functions and uses. HR Poly-Iso-Butylene and Poly-Iso-Butylene are being used interchangeably. HR Poly-Iso-Butylene is only a type of Poly-Iso-Butylene and thus like article to the product under investigation and the product being manufactured by the Domestic Industry.

In view of the same, the Authority holds that Poly-Iso-Butylene being produced by the domestic industry and those being imported from the subject countries can be used interchangeably and thus are commercially and technically substitutable and therefore, are like articles within the meaning of the Rules.

G. DOMESTIC INDUSTRY:

9. The petition has been filed by M/s. Kothari Sugars & Chemicals Limited, Manali, Chennai. The petitioner accounts for more than 25% of the Domestic production during the Period of Investigation of the subject goods in India. Further after initiation of the investigation two Indian manufacturers of the subject goods namely M/s Kochi Refineries Ltd., and M/s Indian Petrochemicals Corporation Ltd., (IPCL) have submitted their support to the petition for imposition of the Anti Dumping Duty on the import of the subject goods from the subject countries. Accordingly, the Authority holds that the petitioner fulfils the requisite criteria to represent the domestic industry, as required under Rule 5(a) and (b) and Rule 2(b).

H. NORMAL VALUE, EXPORT PRICE AND DUMPING MARGIN

10. Under Section 9A(1)(c), normal value in relation to an article means:-
- (i) The comparable price, in the ordinary course of trade, for the like article when meant for consumption in the exporting country or territory as determined in accordance with the rules made under sub-section(6); or

- (ii) When there are no sales of the like article in the ordinary course of trade in domestic market of the exporting country or territory, or when because of the particular market situation or low volume of the sales in the domestic market of the exporting country or territory, such sales do not permit a proper comparison, the normal value shall be either:-
- (iii) Comparable representative price of the like article when exported from the exporting country or territory or an appropriate third country as determined in accordance with the rules made under sub-section (6); or
- (iv) The cost of production of the same article in the country of origin along with reasonable addition for administrative, selling and general costs and for profits, as determined in accordance with the rules made under sub-Section(6);

Provided that in the case of import of the article from a country other than the country of origin and where the article has been merely transshipped through the country of export or such article is not produced in the country of export or there is no comparable price in the country of export, the normal value shall be determined with reference to its price in the country of origin.

- (vi) The Authority provided opportunity to the exporters from subject countries to furnish information relevant to the investigations and offer comments, if any, in accordance with the Section cited above. The Authority wrote to the Embassies/High Commissions of subject countries in India also.

11. TERRITORY OF EUROPEAN UNION

(a) NORMAL VALUE

The Authority notes that the none of the exporters/producers from the Territory of European Union have provided the information as per the prescribed questionnaire. M/s. Bayer, Germany has however offered comments which have been considered above.

The Normal Value was determined at the time of initiation of the investigations on the basis of the constructed cost of production of Poly-Iso-Butylene as provided by the petitioner. The Authority adopts the same for preliminary determination Accordingly, the Normal Value of Poly-Iso-Butylene for all exporters from Territory of European Union has been taken at US\$ **** per MT.

(b) **EXPORT PRICE:**

None of the exporters from Territory of European Union has submitted details of export price in reply to the Questionnaire. The Authority has adopted the export price based on DGCI&S, Calcutta statistics. Ocean freight, insurance, inland freight, port charges and commission to an extent of ****, ****, ****, **** and **** \$/MT respectively based on the claim of the petitioner has been considered. The Ex-factory export price in the Period of Investigation thus works out to **** \$/MT.

12. **BRAZIL:**

(a) **NORMAL VALUE:**

The Authority notes that the none of the exporters/producers from Brazil has provided the information as per the prescribed questionnaire.

The Normal Value was determined at the time of initiation of the investigations on the basis of the constructed cost of production of Poly-Iso-Butylene as provided by the petitioner. The Authority adopts the same for preliminary determination. Accordingly, the Normal Value of Poly-Iso-Butylene for all exporters from Brazil has been taken at US\$ **** per MT.

(b) **EXPORT PRICE:**

None of the exporters from Brazil has submitted details of export price in reply to the Questionnaire. The Authority has adopted the export price based on DGCI&S, Calcutta statistics. Ocean freight, insurance, inland freight, port charges and commission to an extent of ****, ****, ****, **** and **** \$/MT respectively based on the claim of the petitioner has been adopted. The Ex-factory export price in the Period of Investigation thus works out to **** \$/MT.

13. **JAPAN**

(a) **NORMAL VALUE**

The Authority notes that the none of the exporters/producers from Japan has provided the information as per the prescribed questionnaire.

The Normal Value was determined at the time of initiation of the investigations on the basis of the constructed cost of production of Poly-Iso-Butylene as provided by the petitioner. The Authority adopts the same for preliminary determination. Accordingly, the Normal Value of Poly-Iso-Butylene for all exporters from Japan has been taken at US\$ **** per MT.

(b) **EXPORT PRICE:**

None of the exporters from Japan has submitted details of export price in reply to the Questionnaire. Based on the claim of the Petitioner the Authority has determined the weighted average export price on the basis of the prices offered by the exporters from Japan to M/s Indian Oil Corporation and the export statistics based on DGCI&S, Calcutta for the Period of Investigation. The Authority has adopted ocean freight, insurance, inland freight, port charges and commission to an extent of ****, ****, **** and **** \$/MT respectively based on the claim of the petitioner. The Ex-factory export price in the Period of Investigation thus works out to **** \$/MT.

14. **KOREA R.P.;**

M/S. DAELIM CORPORATION, SEOUL, KOREA.

(a) **NORMAL VALUE**

The Authority notes that the exporter/producer has provided the requisite information as per the prescribed questionnaire. The exporter has provided invoice wise details of sales of the subject goods in Korea R.P.; during the Period of Investigation. On the basis of the cost of production details claimed by the exporters, sales in the Domestic markets are above the cost of production and are therefore considered to be in the ordinary course of trade for the purpose of preliminary findings. Subject to verification the Authority has also considered the adjustment as indicated by exporter/producer. The weighted average Ex-factory domestic selling prices comes to **** US\$/MT in Period of Investigation.

(b) **EXPORT PRICE:**

The Authority notes that the exporter/producer has provided the transaction wise details of export sales to India of the subject goods during the Period of Investigation. The exporter/producer has indicated in the sales price structure for export to India various adjustment of export price viz. discounts/commission, packing, inland freight, ocean freight, shipping charges etc. The Authority for the purpose of preliminary findings considers the adjustments as indicated by the exporter/producer.

The weighted average ex-factory export price for the subject goods to India comes to **** \$/MT.

15. **OTHER EXPORTERS/PRODUCERS OF KOREA R.P.:**

(a) **NORMAL VALUE**

As no other exporter/producer from Korea R.P. has provided the information, the Authority has adopted the weighted average domestic sales price as indicated by other cooperating exporter for assessing the normal value. The normal value in case of other exporter/producers of Korea R.P. for the subject during the POI comes to **** \$/MT.

(b) **EXPORT PRICE**

The Authority has adopted the least of the export price to India as provided by the cooperative exporter from Korea R.P. without any adjustment on ocean freight, insurance, commission etc. The ex-factory export price in the Period of Investigation comes to **** US\$/MT

16. **SINGAPORE**

(a) **NORMAL VALUE**

The Authority notes that the none of the exporters/producers from Singapore has provided the information as per the prescribed questionnaire.

The Normal Value was determined at the time of initiation of the investigations on the basis of the constructed cost of production of Poly-Iso-Butylene as provided by the petitioner. The Authority adopts the same for preliminary determination. Accordingly, the Normal Value of Poly-Iso-Butylene for all exporters from Singapore has been taken at US\$ **** per MT.

(b) **EXPORT PRICE:**

None of the exporters from Singapore has submitted details of export price in reply to the Questionnaire. Based on the claim of the Petitioner the Authority has determined the weighted average export price on the basis of the prices offered by the exporters from Singapore to M/s Indian Oil Corporation and the export statistics based on DGCI&S, Calcutta for the Period of Investigation. The Authority has adopted ocean freight, insurance, inland freight, port charges and commission to an extent of ****, ****, ****, **** and **** \$/MT respectively based on the claim of the petitioner. The Ex-factory export price in the Period of Investigation thus works out to **** \$/MT.

17. **THAILAND**(a) **NORMAL VALUE**

The Authority notes that the none of the exporters/producers from Thailand has provided the information as per the prescribed questionnaire.

The Normal Value was determined at the time of initiation of the investigations on the basis of the constructed cost of production of Poly-Iso-Butylene as provided by the petitioner. The Authority adopts the same for preliminary determination. Accordingly, the Normal Value of Poly-Iso-Butylene for all exporters from Thailand has been taken at US\$ **** per MT.

(b) **EXPORT PRICE:**

None of the exporters from Thailand has submitted details of export price in reply to the Questionnaire. The Authority has adopted the export price based on DGCI&S, Calcutta statistics. Ocean freight, insurance, inland freight, port charges and commission to an extent of ****, ****, ****, **** and **** \$/MT respectively based on the claim of the petitioner. The Ex-factory export price in the Period of Investigation thus works out to **** \$/MT.

DUMPING-COMPARISON OF NORMAL VALUE AND EXPORT PRICE

18. The rules relating to comparison provides as follows:-

"While arriving at margin of dumping, the Designated Authority shall make a fair comparison between the export price and the normal value. The comparison shall be made at the same level of trade, normally at ex-works level, and in respect of sales made at as nearly possible the same time.

Due allowance shall be made in each case, on its merits, for differences which affect price comparability, including differences in conditions and terms of sales, taxation, levels of trade, quantities, physical characteristics, and any other differences which are demonstrated to affect price comparability”

The authority has carried out comparison of weighted average normal value with the weighted average ex-factory export price for evaluation of dumping margin.

The dumping margins for the producers/exporters of the subject goods in the subject countries are as under:-

COUNTRY-WISE EXPORTERS/ PRODUCERS	NORMAL VALUE (\$/MT)	EXPORT PRICE (\$/MT)	DUMPING MARGIN(%)
<u>KOREA R.P.</u>			
(i) M/S.DAELIM CORPORATION LTD.,	****	****	15.72%
(ii) ALL OTHER EXPORTERS/PRODUCERS	****	****	46.29%
ALL EXPORTERS/ PRODUCERS FROM			
(i) TERRITORY OF EUROPEAN UNION	****	****	18.03%
(ii) BRAZIL	****	****	44.63%
(iii) JAPAN	****	****	57.23%
(iv) THAILAND	****	****	19.09%
(v) SINGAPORE	****	****	34.36%

The above dumping margins are above the de minimus limits.

J. INJURY:

19. Under Rule 11 supra, Annexure –II, when a finding of injury is arrived at, such finding shall involve determination of the injury to the domestic industry, “.... taking into account all relevant facts, including the volume of dumped imports, their effect on prices in the domestic market for like articles and the consequent effect of such imports on domestic producers of such articles....” In considering the effect the dumped imports on prices, it is considered necessary to examine whether there has been a significant price undercutting by the dumped imports as compared with the price of the like article in India, or whether the effect of such imports is otherwise to depress prices to a significant degree or prevent price increases, which otherwise would have occurred, to a significant degree.

For the examination of the impact of the dumped imports on the domestic industry in India, indices having a bearing on the state of the industry as production, capacity utilisation, sales quantum, stock, profitability, net sales realisation, the magnitude and margin of dumping, etc. have been considered in accordance with Annexure II(iv) of the rules supra.

K. CUMULATIVE ASSESSMENT OF INJURY

20. Annexure II (iii) under Rule 11 supra further provides that “in case where imports of a product from more than one country are being simultaneously subjected to Anti Dumping investigation, the Designated Authority will cumulatively assess the effect of such imports, only when it determines that the margin of dumping established in relation to the imports from each country is more than two percent expressed as percentage of export price and the volume of the imports from each country is three percent of the imports of the like article or where the export of the individual country is less than three percent, the imports cumulatively accounts for more than seven percent of the imports of like article, and cumulative assessment of the imports is appropriate in light of the conditions of competition between the imported article and the like domestic articles”

The Authority notes that the margin of dumping and quantum of imports from subject countries are more than the limit prescribed above. Cumulative assessment of the effect of the imports from Territory of European Union, Brazil, Japan, Korea R.P., Singapore and Thailand are appropriate since the export prices from these countries were directly competing with the prices offered by the Domestic Industry in the Indian market and displacing domestic producers here.

21. All economic parameters affecting the Domestic Industry as indicated above such as production capacity utilisation, sales volume etc. have been examined as under:-

(a). **QUANTUM OF IMPORTS AND MARKET:**

The information with regards to quantum of imports of Poly-Iso-Butylene has been based on information published by DGCI&S, Calcutta. The Authority notes that the market share of imports of the subject goods from the subject countries cumulatively was 73.60% during 1999-2000. The same has increased to 86.62% during the Period of Investigation. The total imports have increased by about 13% during the Period of Investigation over 1999-00.

(b) **PRODUCTION:**

The total production of petitioner company of subject goods during 1999-00 was 6111 MT decreased to 5648 MT (Annualised basis) during the Period of Investigation representing a decrease of about 7.58%.

(c) **SALES VOLUME:**

Total sales volumes of petitioner company during 1999-00 was 6392 MT, which decreased to 5217 MT (annualised basis) during the Period of Investigation showing a decrease of about 18.38%.

(d) **CAPACITY UTILIZATION:**

The petitioner attained an average capacity utilisation of 81.48% in the year 1999-00, which decreased to 75.31% during the POI.

(e) **SALES REALISATION:**

The average sales realisation of petitioner companies from sale of subject goods in domestic market during the year 1999-00 was Rs. **** per MT, which increased to Rs. **** per MT in 2000-01 representing an increase of 5.26%. However the average sales realisation during the last five months of the period of investigation decreased to ****. This shows a steep decline of domestic sales realisation with in the Period of Investigation itself. However it has further been observed that the average Cost of Production of the subject goods has increased during the Period of Investigation over 1999-00 by Rs. **** per Mt. Accordingly the increase in sales realisation during the Period of Investigation has not compensated the increase in cost of production during the same period over the last year.

(f) **PROFITABILITY:**

It has been observed that the petitioner was earning a net profit of Rs.**** per MT of subject goods during 1999-00. However during the Period of Investigation, the petitioner incurred a loss of Rs.**** per MT from the subject goods.

(g) **EVIDENCE OF LOST CONTRACT**

The Domestic Industry would loose contracts due to significantly lower prices quoted by the exporters in the tender floated by M/s Indian Oil Corporation. Even the sole tender wherein the petitioner is lowest priced would result in significant loss to the Domestic Industry .

(h) **CLOSING STOCK**

Closing stock of the Domestic Industry during the Period of Investigation over 1999-2000 has increased substantially from **** Mt to **** Mt. showing an increase of 351 %.

L. **CAUSAL LINK:**

- 22.(a) The Authority after careful examination of the cost of production of the Domestic Industry and the landed value of the exports from subject countries notes that in case of Territory of European Union (EU), and Thailand the average landed value of exports during the Period of Investigation is more than the Non Injurious Price worked out for the Domestic Industry .Accordingly no causal link is established between the exports from these countries and the material injury caused to the Domestic Industry. The Authority notes that Poly-Iso-Butylene has been exported to India from remaining countries namely; Brazil, Japan, Korea R.P. and Singapore at a price below its Normal Value.
- (b) The Authority holds that the weighted average export price in US\$ terms from the subject countries as reported by the DGCIS and as quoted in the tender floated by the Indian Oil Corporation has significantly declined. The petitioner company suffered a decline in sales price during the Period of Investigation itself inspite of increase in cost of production. The petitioner company was selling the subject goods at a profit earlier were able to sell the same in domestic market during the period of investigation only at substantial losses. All these parameters cumulatively indicate that the petitioner company has suffered material injury and the injury to petitioner companies has been caused due to dumped imports of subject goods.

M. INDIAN INDUSTRY'S INTEREST & OTHER ISSUES:

23. (a) The purpose of Anti Dumping Duties, in general, is to eliminate dumping which is causing injury to the petitioner company and to re-establish a situation of open and fair competition in the Indian market, which is in the general interest of the country.

(b) The Authority recognizes that the imposition of Anti Dumping Duties might affect the price levels of the products manufactured using the subject goods and consequently might have some influence on relative competitiveness of these products. However, fair competition on the Indian market will not be reduced by the Anti Dumping measures, particularly if the levy of the Anti Dumping Duty is restricted to an amount necessary to redress the injury to the petitioner company. On the contrary, imposition of Anti Dumping measures would remove the unfair advantages gained by dumping practices, would prevent the decline of the petitioner companies and help maintain availability of wider choice to the consumers of Poly-Iso-Butylene. Imposition of Anti Dumping measures would not restrict imports from the subject countries in any way, and, therefore, would not affect the availability of the product to the consumers.

N. CONCLUSIONS:

24. It would be seen, after considering the foregoing, that:

(a) Poly-Iso-Butylene originating in or exported from subject countries have been exported to India below Normal Value, resulting in dumping;

(b) The Indian industry has suffered material injury only from exports of subject goods from Brazil, Japan, Korea R.P. and Singapore;

(c) The injury has been caused cumulatively by the imports from Brazil, Japan, Korea R.P. and Singapore;

25. It is considered necessary to impose Anti-Dumping Duty, provisionally, pending final determination, on all imports of Poly-Iso-Butylene originating in or exported from Brazil, Japan, Korea RP and Singapore pending final determination.

26. It was considered whether a duty lower than the dumping margin would be sufficient to remove the injury. The average landed price of the imports, for the purpose, was compared with the Non-injurious price of the petitioner company, determined for the period of investigations. Wherever the difference was less than the dumping margin, a duty lower than the dumping margin is recommended. Accordingly, it is proposed that provisional Anti Dumping Duty equal to the difference between the amount indicated in column (2) below and the landed value of imports be imposed from the date of notification to be issued in this regard by the Central Government, on all grades of subject goods originating in or exported from Brazil, Japan, Korea RP and Singapore falling under Chapter 39 or any other Chapter of the Customs Tariff Act, 1975, pending final determination.

COUNTRY-WISE EXPORTERS/ PRODUCERS (1)	AMOUNT IN US\$ PER MT (2)
<u>KOREA R.P.</u>	
(ii) M/S.DAELIM CORPORATION LTD.,	1037.77
(ii) ALL OTHER EXPORTERS /PRODUCERS	1037.77
ALL EXPORTERS/ PRODUCERS FROM	
(i) TERRITORY OF EUROPEAN UNION	N.A.
(ii) BRAZIL	1037.77
(iii) JAPAN	1037.77
(iv) THAILAND	N.A.
(v) SINGAPORE	1037.77

27. Landed value of imports for the purpose shall be the assessable value as determined by the customs under the Customs Act, 1962 and all duties of customs except Additional duty of Customs levied under Section 3, 3A, 8B, 9 and 9A of the Customs Tariff Act, 1975.

O. FURTHER PROCEDURE:

28. The following procedure would be followed subsequent to notifying the preliminary findings:-
- (a) The Authority invites comments on these findings from all interested parties and the same would be considered in the final finding;
 - (b) Exporters, importers, petitioner and other interested parties known to be concerned are being addressed separately by the Authority, who may make known their views, within forty days from the date of the dispatch of the letter. Any other interested party may also make known its views within forty days from the date of publication of these findings;
 - (c) The Authority would conduct further verification to the extent deemed necessary;
 - (d) The Authority would disclose essential facts before announcing final findings.

L. V. SAPTHARISHI, Designated Authority